

## भारतीय लोकतंत्र में राजनैतिक दल की बदलती भूमिका – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रा. डॉ. शशिकांत जे. चवरे, सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग न. मा. द. महाविद्यालय गोंदिया

### सारांश

राजतंत्र सामंतशाही का विरोध करने के लिए पाश्चात्य राजनैतिक धरातल पर सुविख्यात विभिन्न क्रांतियाँ हुईं। जॉन लॉक, मिल, रूसो आदि पाश्चात्य राजनैतिक चिंतकों ने स्वतंत्रता को अहम स्थान दिया। फ्रेंच राजनैतिक क्रांति का स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता यह नारा था जनमत के सामने राजतंत्र एवं सामन्त तंत्र को झुकना पड़ा। पुंजिवाद का उगम हुआ और इसका विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग का उगम हुआ। यही से प्रतिनिधिक शासन प्रणाली की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अनेक युरोपिय देशों ने लिखित संविधान के माध्यम से शासन को संचालित करने की परंपरा का आगाज किया। किंतु प्रतिनिधिक शासन प्रणाली को यथार्थ में लाने हेतु राजनैतिक दल की भूमिका के बारे में वे आशंकित थे। इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में राजनैतिक दल का स्पष्ट तौर पर प्रावधान नहीं किया था। अमेरिका के संविधान निर्माताओं के बहुतांश सदस्यों ने राजनैतिक दल का कड़ा विरोध किया था। फेडरेलिज्म एवं एन्टी फेडरेलिज्म इस आधार पर ना चाहते हुये राजनैतिक दलों ने अमेरिका में दस्तक दी।

वॉशिंगटन, जेफरसन, गांधीजी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे आदि राजनैतिक चिंतकों ने राजनैतिक दल के बारे में जो आशंका व्यक्त की थी वह वास्तविक धरातल पर सत्य प्रतीत हुई। किंतु जिस तरह से भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दशकों के बाद राजनैतिक दल के सदस्यों का नैतिक अधःपतन हुआ वैसे हालात अमेरिका में पैदा नहीं हुये। इंग्लैंड में अलिखित संविधान होने के बावजूद राजनैतिक दल ने जिस भूमिका का वहन किया उसी कारणवश इंग्लैंड के लोकतंत्र की गरिमा अभी भी दिखाई देती है। वहाँ के विपक्ष को जो सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त है, वैसी प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए भारत को और इंतजार करना पड़ेगा।

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 19-3 के अनुच्छेद नुसार जो राजनैतिक दल स्थापित हुये हैं उनमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं पंजीकृत राजनैतिक दल हैं। सत्ता प्राप्त करना यह राजनैतिक दल का प्रमुख स्वाभाविक उद्देश होता है। इसके साथ-साथ नागरिकों को राजनैतिक दृष्टीकोन से जागरूक करने की प्रमुख जिम्मेदारी भी होती है। जनहित के लिए बहुमत की सरकार होना आवश्यक है किंतु राजनैतिक निर्णय निर्धारण में विपक्ष के विरोधी स्वर को नजरअंदाज करना यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चीज है। गांधीजी ने संसदीय शासन प्रणाली के उपर जो आलोचना की थी वह सत्य प्रतीत होती है। बहुमत के आधार पर राजनैतिक दल बहुत से विधेयकों को ध्वनी मत से पारित करते हैं। स्वतंत्रतापूर्व राजनैतिक दल की भूमिका एवं स्वतंत्रता पश्चात राजनैतिक दल की भूमिका इसमें बहुत अंतर आ गया है। येनकेन प्रकारे सत्ता प्राप्त करने के लिए मतदारों को मुर्ख बनाने का काम राजनैतिक दल करते दिखलाई देते हैं। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति में जो राजनैतिक घटनाक्रम हुआ उससे राजनैतिक स्तर अपने निम्न स्तर पर किस तरह गया है उसका एहसास होता है।

### संशोधन विषय का उद्देश

चयनित संशोधन विषय का उद्देश निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया है।

1. आधुनिक लोकतंत्र से परिचित करवाना।

2. लोकतंत्र में राजनैतिक दल की अहमियत समझना ।
3. राजनैतिक दलों के गुण एवं दोषों को उजागर करना ।
4. राजनैतिक दलों के बदलते परिपेक्ष को बतलाना ।
5. महाराष्ट्र के 15 वे विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों की नैतिकता के स्तर को उजागर करना ।

#### संशोधन विषय की परिकल्पना

किसी भी चयनित संशोधन विषय को योग्य दिशा में मोड़ने हेतु परिकल्पना निर्धारित करना आवश्यक है ।

प्रस्तुत संशोधन विषय की परिकल्पना निम्नलिखित है-

1. राजनैतिक दल के अभाव में आधुनिक लोकतंत्र संचालित हो सकता है ।
2. स्वतंत्रतापूर्व एवं पश्चात भारत के राजनैतिक दलों में खिलाडीवृत्ती का भाव है ।
3. चुनाव के मौसम में विभिन्न राजनैतिक दलों में कार्यकर्ताओं का आवागमन होता है ।
4. निर्धारित राजनैतिक दल से सदस्य राष्ट्रीय एवं राज्य हितों के लिए दल बदल करते हैं ।
5. 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति स्तर के बदलते स्वरूप को प्रस्तुत करने का उत्तम उदाहरण है ।

#### संशोधन विषय की पध्दती

प्रस्तुत संशोधन विषय संबंधी जानकारी इकट्ठा करने हेतु द्वितीय स्रोतों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है अखबार, ग्रंथसंपदा, संकेतस्थल, मॅगझीन आदि दस्तावेजों से जानकारी इकट्ठा की गयी है । चयनित संशोधन विषय को न्याय देने हेतु अनुभवि, जानकार, राजनैतिक विद्वानों से चर्चा की गयी है एवं आम नागरिकों की राजनैतिक दलों के प्रति राय ली गयी है ।

#### संशोधन विषय का महत्व

चयनित संशोधन विषय का महत्व नीचे प्रगट किया गया है ।

1. संशोधन विषय के अध्ययन से राजनैतिक दलों की आधुनिक लोकतंत्र में अहमियत समझने में लाभ होगा ।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान परिपेक्ष तक राजनैतिक दल के भूमिका को समझने में मदद होगी ।
3. विचारधारा से राजनैतिक दलों की बढती दूरिया समझने हेतु चयनित संशोधन विषय लाभकारी होने की संभावना है ।
4. महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी विचारधारा से प्रेरित राज्य में राजनैतिक दल के बदलती भूमिका संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त होगी ।

#### प्रस्तावना

लोकतंत्र यह केवल शासन का प्रकार नहीं तो वह समाज का प्रकार भी है । लोकतंत्र इस संज्ञा से भारत का वास्ता हजारों साल से पडा है । एकतंत्र कुलीनतंत्र एवं अभिजात गणतंत्र मे शासन की धुरा जिनके पास थी वे भी लोकतंत्र के प्रशंसक थे । प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत के इतिहास मे शासनतंत्र के उपर लगाम था । इसके पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं । किंतु उस समय मानवतावाद का अभाव था । इस कारणवश, लोकतंत्र के तरफ देखने का नजरिया बहुत अनोखा था ।

वैसे तो भारत 11 वी से 20 वी शताब्दी के मध्य तक विदेशी सत्ता के गुलामी मे था । किंतु ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में अंग्रेजो ने जिस तरह से भारत के शासन को संचालित किया उसी से राजनैतिक दल का

जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीयों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 20 वीं शताब्दी के तिसरे दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक सामाजिक संघटना की भूमिका बखूबी निभाई। आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता पूर्व के, चुनावी दंगल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनैतिक दल की भूमिका भी बेहतर ढंग से निभायी। उस दौर में राजनैतिक दल की परिभाषा प्रस्तुत करनेवाले विद्वानों के अभिप्राय से तत्कालीन राजनैतिक दल की भूमिका मेल खाती है।

26 जनवरी 1950 को भारत संविधान अमल में लाया गया। 1952 में पहला सार्वजनिक चुनाव हुआ उस वक्त करिबन 14 राजनैतिक दल थे आज राजनैतिक दलों की संख्या हजारों में हो गयी है। अंग्रेजी उपनिवेश काल में भारत के राजनैतिक दलों ने जो कार्य किया क्या? वैसा ही कार्य राजनैतिक दल स्वतंत्रता पश्चात से वर्तमान काल में भारत के लोकतंत्र के यात्रा में निभा रहे हैं इसको टटोलना अत्यंत आवश्यक है। फुले, शाह, आंबेडकर की कर्मभूमि कहलाने वाले महाराष्ट्र में राजनैतिक दलों की भूमिका किस तरह की है और महाराष्ट्र की राजनीति भविष्य में किस तरह करवट लेगी इन प्रश्नों को खंगालने हेतु राजनैतिक पक्ष का अर्थ, परिभाषा भारत के लोकतंत्र की यात्रा, राजनैतिक अनुभव, विभिन्न विचारों के राजनैतिक दलों के संबंधी विचार वर्तमान परिपेक्ष में राजनैतिक दल की बदलती भूमिका 2019 से 2024 में महाराष्ट्र के राजनीति में आए राजनैतिक भुंकप इन सभी को जोड़कर अध्ययन करने के बाद ही राजनैतिक दलों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कैसी है। इन प्रश्नों का सटिक उत्तर मिलने में मदद होगी। उस संबंध में मुद्दों से संबंधित चर्चाओं का दौर आगे जारी रहेगा।

#### अ) भारत की लोकतांत्रिक यात्रा

विकास यह निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। आधुनिक लोकतंत्र में आज हम जो खुली हवा में स्वतंत्रता, समता इस आधार पर साँस ले रहे हैं वह इतिहास का प्रतिफल है। राजनीतिक निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में वयस्क, प्रौढ मताधिकार के माध्यम से जो प्रवेश हुआ है उसका प्रदिर्घ इतिहास है। इस इतिहास के पन्ने पलटकर देखने पर ही आधुनिक लोकतंत्र को समझने में सहायता होगी। वर्तमानकालीन भारत के गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के जो अस्तित्व आज है, उसके चिन्ह प्राचीन इतिहास में दिखाई देते हैं। गण इस शब्द का उल्लेख "ऋग्वेद में 40, अथर्ववेद में 6, ब्राम्हण ग्रंथों अनेक प्रसंगों में दिखाई देता है।"<sup>1</sup> ऋग्वेद काल में जो सभा और समिती का उल्लेख प्राप्त होता है उसमें भी आधुनिक लोकतंत्र के अनुरूप निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में उपस्थित जनो का सहभाग दिखाई देता है। किंतु उस समय उस समय के लोगों की माँग एवं आज के दौर की आकांक्षाएँ इसमें जमीन आसमान का अंतर होना अति स्वाभाविक है।

आधुनिक लोकतंत्र में 21 वीं शताब्दी में जो राजनीतिक संस्थाएँ दिखाई देती हैं उसी तरह की राजनीतिक संस्थाएँ बौद्धकालीन कालखंडों में अस्तित्व में थीं। जयस्वाल के अनुसार "राजा, उपराजा, सेनापति, भण्डागारिक"<sup>2</sup> आदि राजनीतिक पद का अस्तित्व बौद्धकालीन गणराज्यों में था। इन पदों का चयन योग्यता के आधार पर उपस्थित गण एवं समुहों के द्वारा किया जाता था। उस समय "शाक्याचा, भग्गोचा, वुलीवोचा, कालमोचा, कोलीयोचा, मल्लीचा, मलोचा, मल्लोचा, मौर्यचा, विदेहोचा"<sup>3</sup> आदि गणराज्य अस्तित्व में थे इसके पर्याप्त सबूत बौद्धकालीन साहित्यों में दिखाई देते हैं।

मध्ययुगीन काल को "लॉर्ड ब्राईस"<sup>4</sup> ने राजनीतिक दृष्टिकोण से शुन्य का काल कहा है। ब्राईस के इस कथन में सत्यांश दिखाई देता है। संपूर्ण विश्व में राजतंत्र एवं सामंततंत्र का प्रस्त मध्ययुगीन काल में दिखाई देता है। किंतु भारत के मध्ययुगीन काल में भी लोकतांत्रिक अवशेष अपवाद स्वरूप दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में महात्मा बसवेश्वर जी ने अनुभव मंडप की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। आज के आधुनिक संसद की तरह उसमें 770

सदस्य सम्मिलित थे और यह बड़ा सुखद आश्चर्य है कि इसमें "70 महिलाएँ"<sup>5</sup> सम्मिलित थी। उस दौर के विश्वस्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का राजनीतिक सहभाग कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सलतनत एवं मुगल काल को भारत के लोकतांत्रिक यात्रा के दृष्टिकोन से अलोकतांत्रिक कहना अतिशयोक्ती पूर्ण नहीं होगा।

प्रभावी केंद्रिय सत्ता का अभाव एवं अन्य कमजोरीयों कारण इस्ट इंडिया कंपनीने भारत के उपर 18 वी शताब्दी के मध्यार्थ में राजनीतिक सत्ता प्रस्थापित की। 1857 के बाद कंपनी से क्राऊन के पास सत्ता हस्तांतरित हुयी। शासन संचालित करने के अंदाज में आमूलचुल परिवर्तन हुआ। और उसी का नतीजा 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 आदि शासन सुधार अधिनियमों व्दारा आधुनिक भारत के लोकतंत्र की यात्रा का श्रीगणेश हुआ। और आगे वह विकसित होते गयी। आधुनिक लोकतंत्र का परिचय अंग्रेजों के शासन संचालन के तरिकों के कारण भारतियों को हुआ और उसमें से ही राजनीतिक दलों का दौर प्रारंभ हुआ। 1919 मॉटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून व्दारा वरिष्ठ सभागृह में सदस्य के चयन हेतु 17364 मतदारों को एवं कनिष्ठ सदन के सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु 99874 मतदारों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। उस समय भारत की जनसंख्या 24 करोड थी। मतदान का अधिकार यह मुख्यतः आर्थिक आधारों पर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुयी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के उद्देश्य पत्रिका के अनुसार भारत एक स्वतंत्र, सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मुल उद्देश्य पत्रिका में "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष"<sup>6</sup> इन शब्दों का प्रावधान नहीं है।

#### ब) आधुनिक लोकतंत्र से राजनीतिक दल का संबंध

इंग्लैंड की स्वर्णक्रांती, फ्रान्स की राज्यक्रांती एवं अमेरिका की स्वतंत्र संग्राम की क्रांती आदि घटनाओं में 17 वी एवं 18 वी शताब्दी में लोकतंत्र का परचम बुलंद करने का काम किया। इन्हीं क्रांतियों के कारण प्रतिनिधिक शासन प्रणाली का आगाज हुआ। राजतंत्र एवं सामंतशाही का पतन प्रारंभ हो गया। आधुनिक लोकतंत्र की लोकप्रियता 20 वी शताब्दी के मध्यार्थ में पहुँच गयी। यही से राजनीतिक दलों की आवश्यकता बढ़ने लगी। राजनीतिक दल एवं आधुनिक लोकतंत्र इनका संबंध समझने के लिये प्रथमतः लोकतंत्र को समझना जरूरी है। लोकतंत्र की परिभाषा प्रस्तुत करनेवाले विद्वानों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय परिभाषाओं को दोहराना यहाँ जरूरी है।

1. "अब्राहम लिंकन के अनुसार - लोगों ने लोगों के लिये और लोगों व्दारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है।
2. प्राध्यापक सिली के अनुसार - जिस शासन प्रणाली में लोगों को सक्रिय तौर पर सहभागी होने का मौका मिलता है उसे लोकतंत्र कहते हैं।"<sup>7</sup>

लिंकन एवं सिली ने राजनैतिक निर्णय निर्धारण में जनमत को अहम स्थान दिया है। प्राचीन ग्रीक में भी जनमत को उचित स्थान दिया गया था किंतु उस समय की परिस्थिती एवं 18 वी शताब्दीयों के उपरांत परिस्थितीओं में अंतर है। भौगोलिक सिमाएँ, जनसंख्या, जनजागृती, यातायात की साधन सामृगी, वैज्ञानिक खोज आदि कारणों से प्रतिनिधिक शासन प्रणाली यह समय की माँग थी और उसे चयनित करने हेतु साजनैतिक दल के सिवा कोई चारा नहीं था। प्रतिनिधिक शासन का स्वीकार करनेवाले इंग्लैंड में राजनैतिक दल का उगम वैज्ञानिक आधारों पर नहीं स्वभाविक रूप में विकसित हुआ। आधुनिक लोकतंत्र राजनैतिक दलों के अभाव में किस तरह से संचालित होगा इसकी अभितक खोज नहीं हुयी है इसी कारणवश राजनैतिक दल को ह्युबर ने "लोकतंत्र का तेल"<sup>8</sup> कहा है। जिस तरह कोई भी वाहन बिना इंधन के नहीं चल पायेगा उसी तरह राजनैतिक

दल के अभाव में लोकतंत्र संचालित करना असंभव है। राजनैतिक दल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु राजनैतिक दल के बारे में राजनैतिक विद्वानों ने जो परिभाषाएँ प्रस्तुत की उस में से चुनिंदा परिभाषाओं को समझना ज़रूरी प्रतीत होता है।

1. जोसेफ शुपिंटर के अनुसार- "राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करना और उसे कायम रखने के लिये अन्य राजनैतिक दलों से स्पर्धा करके अपना अलग अस्तित्व निर्माण करने में सदा व्यस्त रहनेवाले समुह को राजनैतिक दल कहते हैं।"<sup>9</sup>
2. एंडमण्ड बर्क - के शब्दों में " राजनैतिक दल कुछ लोगों का एक समुह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिये संगठित रहता है।"<sup>10</sup>

वैश्विक स्तर एवं भारत में साक्षरता का प्रतिशत अपने चरम सिमा पर है। शिक्षा के प्रचार की तेजी विद्युत गती से बढ़ गयी है। अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से विश्व बहुत छोटा हो गया है। शासन का कार्यभार लोककल्याणकारी राज्य के संकल्पना का स्विकार करने के कारण बढ़ गया है। इन परिवर्तनों के कारण आधुनिक लोकतंत्र की पेचीदगियों में वृद्धि हुयी है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन काल जैसे शासन सत्ता में परिवर्तन आज के आधुनिक युग में होना असंभव सी बात है। राजनैतिक दल के अभाव में प्राचीन एवं मध्ययुगीन काल में जिस तरह से रक्तंजित क्रांती एवं युद्ध के द्वारा सत्ता परिवर्तन होता था वैसा ही दौर सुरु हो जायेगा। इसी कारणवश आधुनिक लोकतंत्र में राजनैतिक दल ऑक्सीजन के समान है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र यह निर्वाचन के माध्यम संचालित होता है और जहाँ निर्वाचन हो वहाँ राजनैतिक दल का अस्तित्व होना आवश्यक है। अनुवांशिक सत्ता का दौर चला गया है। उसकी जगह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली है। इसी को ध्यान में रखकर निर्वाचन संबंधी भारत के संविधान में "324 से 329 अनुच्छेद"<sup>11</sup> तक प्रावधान किया गया है।

#### क) राजनैतिक दल के संबंध में विचारकों के विचार एवं अनुभव

सद्शासन प्राप्त करना यह प्राचीन मध्ययुगीन कालखंडों में स्थित शासन का ध्येय था। उस समय के अनुसार विभिन्न साधन एवं तंत्र द्वारा शासन को संचालित करते वक्त जनमत की भावनाओं को पुरी तरह से नज़रअंदाज़ करना इतना आसान नहीं था। सत्ता संचालित करते वक्त उस समय के राजाओं को सद्शासन स्थापना करने हेतु स्वयं एवं जनता को कानूनी नियंत्रण में रखना आवश्यक लगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुये 17 वी एवं 19 वी शताब्दी में पाश्चात एवं भारतीय राजनैतिक चिंतकों ने उदा. हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, गांधीजी इन विभूतियों समाज एवं राज्यों के बीच में समझौता होकर, कुछ शर्तों पर राज्य को बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने की सहूलियत दी थी। निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन से तंग आकर जनमत लोकतंत्रात्मक शासन के प्रति आकर्षित हुआ। व्यक्ति स्वतंत्रता का भाव बढ़ने लगा इसी से प्रतिनिधिक शासन का आगाज हुआ। राजनैतिक चेतना विद्युत गती से फैली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग विभिन्न आधारों पर बढ़ने लगी। उसी शृंखला में अमेरिका का नाम सबसे पहले पंक्ति में रखा जा सकता है।

"अमेरिका के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन"<sup>12</sup> ने राजनैतिक दल का कडा विरोध किया था। उनके साथ अमेरिका के प्रसिद्ध कानून के जानकार जेफरसन भी थे। वाशिंगटन के मतानुसार राजनैतिक दल का प्रावधान संविधान में किया गया तो राजनैतिक दल यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय एकात्मता को खतरा खड़ा कर सकता है। भविष्य में नागरिकों की सत्ता प्राप्त करने हेतु यह राजनैतिक दल किसी भी हद तक जाने की संभावना है। इसलिए "अमेरिका के संविधान में राजनैतिक दलों को स्थान नहीं दिया गया था।" इंग्लैंड में भी राजनैतिक दल को वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। इन दो देशों का आदर्श सामने रखकर भारत के संविधान में

“अनुच्छेद 19-3”<sup>13</sup> के अनुसार संघ एवं समुदाय गठीत करने की स्वतंत्रता है। किंतु मुल संविधान में राजनैतिक दलों के बारे में स्पष्ट तौर पर संविधानिक प्रावधानों का अभाव दिखाई देता है।

राजनैतिक दल में विभिन्न गुणों के साथ मुलभुत दोष भी दिखाई देते हैं किंतु शासन व्यवस्था का रूप, सहरचना, संघटन कैसे भी हो राजनैतिक दल के अभाव में शासन को संचालित करना आधुनिक युग में असंभव है। सहसंघात्मक, अध्यक्षात्मक एवं साम्यवादी देशों में ऐतिहासिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार एक दलीय, विदलीय एवं बहु दलीय राजनैतिक दल व्यवस्था है पर राजनैतिक दल की भूमिका के बारे में राजनैतिक विचारकों ने जो संदेह व्यक्त किया है उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। “विनोबा भावे”<sup>14</sup> जी के मतानुसार संसदिय शासन प्रणाली जो दल प्रणाली पर आधारभुत है यह शासन सत्ता का दुरुपयोग, गुंडागर्दी एवं भ्रष्टाचार इन अलंकारों से सुशोभित है। लोकतंत्र एवं चुनाव यह एक ही सिक्के के दो पहलु है। चुनावी दंगल में किसी ना किसी राजनैतिक दल की पटकनी होगी। कोई सत्ता में विराजमान होगा तो किसी को विपक्ष में बैठना होगा। हालांकि शासन को संचालित करने का महत्वपूर्ण काम सत्तारूढ दल करता है। किंतु उसकी शासन सत्ता को निरंकुश होने से रोकने का काम विपक्ष बखुबी कर सकता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए “सर आयव्हर जेर्निंग”<sup>15</sup> ने विपक्ष की भुमिका को अहम् स्थान दिया है। किंतु विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाते वक्त गैरज़रूरी वक्तव्य, सभा त्याग एवं घेराव इससे बचना चाहिए। इन साधनों का उपयोग राष्ट्रीय हितों के आधार पर करना चाहिए ऐसा सुझाव संविधान के शिल्पकार “डॉ. बी.आर. आंबेडकर जी”<sup>16</sup> ने दिया है।

सदशासन एवं सुशासन निर्माण करना यह आंतरिक चुनौती हर दौर में दिखाई देती है। अन्याय एवं अत्याचार करनेवाला निरंकुश राजा, प्रजा के हाथों से छुट जाने के उदाहरणों से इतिहास भरा पडा है। क्योंकि राजा के सुसंघटित प्रभाव के सामने प्रजा असंघटित थी। प्रबोधन युग की चिंगारी ने सामाजिक क्रांति की मशाल जलाई। जनता ने राजतंत्र के आतंक को खत्म करवाने हेतु लोकतंत्र को आमंत्रित किया है। लोकतंत्र के साथ संसदिय शासन प्रणाली भी उपजी पर इसे संचालित करवाने के लिये राजनैतिक दल यह सामाजिक क्रांति का माध्यम होगा क्या ? यह प्रश्न है। राजनैतिक दल ने प्रबोधन के माध्यम से नागरिकों के बीच दुरिया कम करनी चाहिए पर राजनैतिक रोटी सेखने के लिये दुरिया बढ़ाने का काम दल प्रणाली करते हुये दिखाई देती है। इसका गांधीवादी विचारों के अनुयायियों ने खुलकर विरोध किया है। “जयप्रकाश नारायण जी”<sup>17</sup> के अनुसार राजनैतिक दल संपत्ती, संघटना एवं प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को लुभाते हैं, भ्रमित करते हैं, जोर जबरदस्ती से अपनो मतों को थोपते हैं। इसी कारणवश वर्तमान परिपेक्ष लोकतंत्र यह दलीयतंत्र बन गया है। जो जनप्रतिनिधी जनता के समस्याओं को संसद में रखता है, उनका चयन करने में राजनैतिक दलों की भुमिका अहम होती है। मतदार केवल राजनैतिक दलों व्दारा थोपे गये चुनावी उमेदवारों को अपना समर्थन देती है।

### ड) स्वतंत्रतापूर्व एवं पाश्चात्य राजनैतिक दलों की स्थिति

उन्नत शासन के लिए जनमत की प्रतिक्रिया प्राप्त करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान मे रखकर ब्रिटिश सरकारने “1985”<sup>18</sup> मे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को गठीत करने का काम किया। आगे चलकर इसी मंच से ब्रिटिश सरकार को उनके कामकाज संबंधी जनता के प्रतिसाद की जानकारी इकट्ठा करने मे बहुत सहायता हुयी। 1937 के पहले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की भुमिका राजनैतिक दल से ज्यादा सामाजिक संघटन के रूप मे थी। 1937 के बाद चुनावी दंगल मे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने बढचढकर हिस्सा लिया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को जाता है। ऐसी छवी स्वतंत्रता पश्चात भारतीयों में निर्माण

हुयी थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में करिबन 14 राजनैतिक पक्ष थे। इसीलिए 1952 से लेकर, 1984 तक लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का ही बोलबाला था।

1977 से 1980 में जनता पार्टी ने केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की लेकिन राजनैतिक स्वार्थ के कारण जनता पार्टी कुछ ही सालों में फुट गया इसमें सम्मिलित जनसंघ के नेताओं ने "1980"<sup>19</sup> में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1990 के बाद भारतीय राजनैतिक कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी इस प्रमुख राजनैतिक दलों के इर्दगिर्द मंडराती हुयी दिखाई देती है। इन प्रमुख दलों का गुट ही केंद्र एवं बहुतांश राज्यों में राजनैतिक सत्ता पर हावी है। हालांकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में बहुदल प्रणाली निर्माण होना स्वाभाविक है। वर्तमान स्थिति "भारत में 6 राष्ट्रीय दल, 56 प्रादेशिक दल एवं 2796 पंजीकृत राजनैतिक दल"<sup>20</sup> विद्वमान है। बहुदल प्रणाली अस्तित्व में होने के बावजूद इंग्लैंड, अमेरिका जैसे दो दल प्रभावी दिखाई देते हैं। देश की राजनीति विद्वदल प्रणाली के तरफ जाते हुये दिखाई देती है।

### निष्कर्ष एवं मुल्यांकन

श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुकूल, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पर्यावरण निर्माण करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य पर होती है। इसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिये चयनित संशोधन विषय में राजनैतिक दल यह अध्ययन का केंद्र बिंदु थे। उसी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जो विचार विमर्श किया गया उसके आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है।

1. आधुनिक लोकतंत्र को राजनैतिक दल के शिवाय संचालित करना असंभव सा प्रतीत होता है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने के लिये चुनाव अनिवार्य है। जहाँ सार्वत्रिक चुनाव का प्रावधान हो वहाँ राजनीतिक दल अत्यावश्यक है। इसी कारणवश बिना राजनैतिक दल के आधुनिक लोकतंत्र के बारे में सोचना असंभव है।
2. राजनैतिक दल का उगम ब्रिटिश उपनिवेश काल में हुआ किंतु स्वतंत्रता पश्चात कुछ दशकों को छोड़ दिया जाये तो राजनैतिक दल को सदस्यों का नैतिक स्तर का दिन-ब-दिन न्हास हो रहा है।
3. जिस राजनैतिक दल चुनाव में जितने की गारंटी हो ऐसे राजनैतिक दलों में चुनावी मौसम में चुनावी उम्मेदवारों का प्रवेश होता है। दल बदल कानून 1985 के कानूनी प्रावधानों को राजनैतिक दल के अंतर्गत गुटों के अपने आवश्यकता नुसार उपयोग करके कानून की धज्जीयाँ उडायी जाती हैं। उनके इस कार्य को सत्तारूढ पक्ष एवं न्यायालयों ने साथ दिया है यह दिखाई देता है।
4. 'सत्ता' अधिसत्ता में रूपांतरित होने हेतु प्रयासरत रहती है। इसी अधिसत्ता के आकर्षण से आकर्षित होकर मतदारों के आदेश को झुठलाकर विपक्ष सरकारों में सामिल होने के लिये मौके की तलाश में रहता है। इसी कारणवश मजबूत विपक्ष के अभाव में भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।
5. चुनाव लढते वक्त राजनैतिक दल परस्पर विरोधी मुद्दों के आधार पर चुनाव लढते हैं। इसी चुनावी मौसम में मतदार भी राजनैतिक दलों आधार पर विभाजित होता है। शायद यह विभाजन मतदारों में प्रदिर्घकाल तक दिखाई देता है। किंतु आकड़ों की राजनीति के खेल में राजनीतिक दल अपने परस्पर विद्वेश की भावनाओं को दूर रखकर सत्ता का स्वाद चखने हेतु आपस में मिल जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में घटित राजनैतिक घटनाक्रम है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. शर्मा हरीशचंद्र, "प्राचीन भारतीय राजनितिक विचार एवं संस्थाएं", कॉलेज बुक डेपो, जयपूर, 1970, पृ.क्र.238.
2. संपादक त्यागी रुची, "प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का राजनितिक चिंतन", हिंदी माध्यम कार्यान्व निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016, पृ.क्र. 87.
3. त्रिपाठी ममता मणि, "भारत की लोकतांत्रिक यात्रा एवं चुनाव", राधा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली, 2012, पृ.क्र. 20-21.
4. शर्मा उर्मिला व शर्मा एच.के., "पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन", एटलांटिक पब्लिकेशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, 2010, पृ.क्र. 278.
5. मोगलेवार सुधाकर सोमेश्वर, "बसवण्णा", अ.भा. मराठी वीरशैव साहित्य मंडळ, नागपूर, 2005, पृ.क्र. 55.
6. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र. 136.
7. लोटे रा.ज., "राज्यशास्त्रीय सिद्धांत", पिंपळापुरे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, 2010, पृ.क्र. 154.
8. फडिया बी.एल., "तुलनात्मक राजनिति", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृ.क्र.125.
9. हाशम शेख व गवई डॉ. जोगेद्र, "तुलनात्मक शासन आणि राजकारण", विश्व पब्लिशर्स अॅण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स, नागपूर, 2004, पृ. क्र. 210.
10. फडिया बी.एल., "तुलनात्मक राजनिति", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृ.क्र.126.
11. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र.239.
12. लोटे रा.ज., "तुलनात्मक शासन आणि राजकारण" पिंपळापुरे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, 2010, पृ. क्र. 253.
13. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र.119.
14. भोळे भाष्कर लक्ष्मन, "आधुनिक भारतातीतल राजकीय विचार", पिंपळापुरे अॅण्ड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर, 2003, पृ. क्र.500.
15. गोस्वामी भालचंद्र, "लोकतंत्र व विधानमंडल", पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपूर, 2005, पृ. क्र. 223.
16. भोळे भाष्कर लक्ष्मन, "आधुनिक भारतातीतल राजकीय विचार", पिंपळापुरे अॅण्ड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर, 2003, पृ. क्र.835.
17. कित्ता पृ.क्र. 530.
18. शर्मा एच.सी., "भारत में शासन और राजनिति", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ.क्र.38.
19. बंग के.आर., "महाराष्ट्र शासन व राजकारण", विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद, 2013, पृ.क्र.373
20. [www.jagransosn.com](http://www.jagransosn.com)